प्रेषक

राधा रत्डी, सचिव, वित्त उत्तरांचल शासन।

सेवा में.

(1) समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।

विस्त (वै०आ०-सा०नि०)अनुभाग-7 देहरादून, दिनांक। 5 नवम्बर, 2006

विषय:-दिनांक 01.01.1986 से पूर्व रू० 470-735 के वेतनमान में कार्यरत आशुलिपिकों के वेतनमान संशोधन विषयक शासनादेश दिनांक 29 जून, 2006 एवं 05 सितम्बर, 2006 का स्पष्टीकरण।

महोदय.

शासनादेश संख्या-109/XXVII(7)/2006, दिनांक 29 जून, 2006 तथा तद्क्रम में निर्गत स्पष्टीकरण विषयक शासनादेश सं0-145 /XXVII(7)/2006, दिनांक 05 सितम्बर, 2006 निर्गत करने के बाद भी आशुलिपिक संवर्ग के विषय में उत्तर प्रदेश शासन के वित्त (वै०आ०) अनु0-2 के पत्र संख्या-वै०आ०-2-904 / दस- 2006, दिनांक 13 सितम्बर, 2006 एवं कतिपय संघों द्वारा यह जिज्ञासा की गयी है कि क्या दिनांक 01.01.1986 से उन सभी आशुलिपिकों को रू0 1350-2200 का वेतनमान अनुमन्य कराया गया है जिन्हें रू० 1200-2040 का वैतनमान पूर्व से अनुमन्य हो चुका है? चूँकि यह प्रकरण पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश से भी सम्बन्धित था और राज्य स्थापना के पूर्व का प्रकरण है, अतः पत्र संख्या 206 / XXVII(7) / 2006, दिनांक 15 सितम्बर, 2006 द्वारा उत्तर प्रदेश को यह स्थिति स्पष्ट की गयी कि माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बैन्च में दायर रिट याचिका संख्या-560 / एसएस / 1992 में पारित उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेशों के क्रम में उत्तर प्रदेश के न्याय विभाग द्वारा निर्गत आदेश संरथा-2468 / सात-न्याय-2-05-33-रिट / 92, दिनांक 5,9.2005 के द्वारा आगु लेपिक संवर्ग के रू० 470-735 के वेतनमान को 1.1.1986 से रू० 1350-2200 किये जाने का आदेश निर्गत किया गया था। याचिका में उ०प्र० शासन के वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के अ०शा० पत्र सं०-वे0:आ0-1-2518 /दस-101(एम) /89 टी०सी०-1, दिनांक 24 जनवरी. 1991 को आधार बनाया गया है, कि दिनांक 1.1.1986 से पूर्व रू० 470-735 के वेतनमान में जिन आशुलिपिकों को रू० 1200-2040 अनुमन्य कराया गया था उन्हें रू० 1350-2200 का वेतनमान अनुमन्य होगा। यद्यपि उक्त आदेश के बाद उ०प्र शासन के अ०शा० पत्र सं०-वै०आ०-1-1311/दस-101 (एम) / ८९, दिनांक १६.०७.१९९३ द्वारा मुख्य सचिव की संस्तुतियाँ पर आशुलिपिक संवर्ग के वेतनमानों को नये सिरे से संशोधित कर दिया गया था, जो मूलतः अधिकारी, जिसके साथ आशुलिपिक सम्बद्ध हो, के वैतनमान

पर आधारित था तथा प्रशासनिक विभागों से अपेक्षा की गयी थी कि अपने विभागों के ढाँचे को तद्नुसार संशोधित कर वित्त विभाग की सहमति शीघ प्राप्त करें।

2- दिनांक 16 जुलाई, 1993 का शासनादेश निर्गत करते समय भी चूँकि रू० 1200-2040 के वेतनमान में आशुलिपिक का पद अस्तित्व में था और अधेकारी, जिसके साथ आशुलिपिक सम्बद्ध / कार्यरत था, पर आधारित बनाया गया था, अतः उत्तरांचल सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि यदि कोई ऐसा आशुलिपिक जो 1.1.1986 से पूर्व रू० 470-735 के वेतनमान में सृजित पद के सापेक्ष नियुक्त किया गया था और अधेकारी जिसके साथ वह आशुलिपिक 1.1.1986 या उसके बाद सम्बद्ध हुआ था, का वेतनमान इस प्रकार हो कि उक्त आशुलिपिक का वेतनमान रू० 1200-2040 ही अनुमन्य कराया गया हो और मात्र ऐसे पदधारकों को 1.1.1986 से रू० 1350-2200 का वेतनमान केवल वैयक्तिक रूप से अनुमन्य कराया जाय। तात्पर्य यह है कि 1.1.1986 के पूर्व के ऐसे आशुलिपिक पदधारक को यह वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य होगा, जब तक कि वह रू० 1350-2200 या इससे उच्च वेतनमान (प्रोन्नित / समयमान वेतनमान के रूप में) प्राप्त न कर ले।

3— वेतन समिति (1997—99) के 14वें तथा 16वें प्रतिवेदन खण्ड—1 व 2 के क्रम में मुख्य सचिव समिति (उ०प्र०) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में मुख्य सचिव समिति (उ०प्र०) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में शासनादेश संख्या अ०शा० पत्र सं0—वे०आ०—2—641/दस—2002—14/2007 टी०सी०, दिनांक 24.04.2002 द्वारा आशुलिपिक संवर्ग हेतु उत्तरांचल के स्टाफिंग पैटर्न शासनादेश संख्या—110/XXVII(7)/2006, दिनांक 29 जून. 2006 द्वारा दिनांक 13.12.2004 से आशुलिपिक संवर्ग में विभागों में उपलब्ध पदों पर निर्धारित अनुपात में लागू किया गया, अर्थात् 1.1.1986 के पूर्व नियुक्त रू० 470—735 के आशुलिपिकों को, अधिकारी जिससे वे सम्बद्ध थे, के वेतनमान के कारण 1.1.1986 से रू० 1200—2040 का वेतनमान दिया गया, हेतु विशेष स्थिति एवं ऐसे कर्मचारियों को हानि न हो, वैयिक्तक रूप यह सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया जो उच्च वेतनमान प्राप्त होने पर स्वतः समाप्त हो जायेगा।

4— उपरोक्त समस्त तथ्यों से स्वतः स्पष्ट है कि आशुलिपिक सवर्ग हेतु

1.1 1986 से विभाग में आशुलिपिक की वरिष्टता को दृष्टि में रखते हुए वित्त
विभाग की सहमति से उसका वेतनमान अधिकारी, जिसके साथ वह सम्बद्ध
हो, के वेतनमान पर आधारित किया गया था तथा 13 दिसम्बर, 2004 से
स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर वेतनमान संशोधित करने का निर्णय लिया
गया। अतः उपरोक्त विषयक शासनादेश दिनांक 29 जून, 2006 तथा 05
सितम्बर, 2006 का तात्पर्य है कि दिनांक 1.1.1986 से पूर्व नियुक्त
आशुलिपिक के वे पदधारक जिन्हें रू० 470—735 का वेतनमान अनुमन्य था
परन्तु 1.1.1986 को जनका वेतनमान 1200—2040 निर्धारित किया गया था,

मात्र उन्हीं पदधारकों को 1.1.1986 से रू० 1350-2200 का वेतनमान वैयक्तिक रूप से देय होगा, जब तक कि उन्हें रू० 1350-2200 या उससे उच्च वेतनमान, प्रोन्नत वेतनमान या समयमान वेतनमान के रूप में न प्राप्त हो जाय।

उपरोक्त स्पष्टीकरण आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ताकि दिये गये अपवाद को छोडकर एवं 13 दिसम्बर, 2004 से लागू आशुलिपिक संवर्ग के वैतनमान की संरचना यथावत् बनी रहे।

> भवदीय, राधा रतूड़ी सचिव, वित्ता।

संख्या-270(1)/XXVII(7)/2006, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

- 1- महालेखाकार उत्तरांचल, देहरादून।
- 2- सचिव, मा० राज्यपाल उत्तरांचल, देहरादून।
- 3- रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तरांचल।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
- 5- समस्त अनुमाग, उत्तरांचल सचिवालय।
- ६- निदेशक, एन०आई०सी० उत्तरांचल एकक, देहरादून।

आज्ञा(से, १८०एन० सिंह) अपर सचिव।